छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक - 7 (अक्टूबर- दिसम्बर 2018)

ईमेलः **chhattisgarh.sccc@gmail.com**

वेबसाइट : **www.cgclimatechange.com**

मुख्य सम्पादक की कलम से.....

सम्माननीय पाठक,

राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र की त्रैमासिक समाचार पत्रिका का यह नया संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रस्तुत अंक में छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय वनमंत्री महोदय का शुभकामना संदेश शामिल है साथ ही इस अंक में पार्टियों के सम्मेलन (COP)के 24वें सत्र के सकारात्मक परिणाम की जानकारी दी गयी है।

राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा धमतरी वनमण्डल में वनोपज समितियों के सदस्यों की क्षमता उन्नयन एवं गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु तीन दिवसीय बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया तथा जलवायु परिवर्तन शाखा के NAFCC परियोजना अंर्तगत धमतरी वनमण्डल के दुगली परिक्षेत्र के जबर्रा,मुनईकेरा तथा दिनकरपुर वन समितियों के वनोत्पादों के प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है ।

इस अंक में हरित दिवाली—स्वस्थ दिवाली अभियान के बारे मे सविस्तार वर्णन किया गया है जिसका शुभारंभ 22 अक्टूबर 2018 को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा किया गया क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण श्वास की बीमारियों से पीडित लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और भी गंभीर हो जाती है। इस अंक में छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ वन मण्डल अंर्तगत छाल खुली खदान परियोजना क्षेत्र में विभिन्न मौसमों में पक्षियों की विविधताओं के अध्ययन की चर्चा की गयी है साथ ही इस संस्करण में, जलवायु परिवर्तन के नन्हें शिकार आदि कुछ लेख भी सम्मिलित किए गए है।

मै आशा करता हूँ कि आपको नया संस्करण पंसद आएगा। अगर आप किसी विषय को आगामी अंक में प्रकाशित कराना चाहते है तो कृपया हमें सूचित करे।

आपके प्रोत्साहन एवं सुझावों की प्रतिक्षा में.....

Shirish

(शिरीष चन्द्र अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं नोडल अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र, रायपुर

विषय-वस्तु

- जलवायु परिवर्तन के नन्हें शिकार
- माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश
- माननीय वन मंत्री जी का संदेश
- पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दिवाली – स्वस्थ दिवाली अभियान का शुभारंभ किया
- वैश्विक रिर्पोट की चेतावनी –भारत को बड़ा खतरा, जलवायु परिवर्तन का असर आशंका से कही ज्यादा बदतर
- पार्टियों के सम्मेलन (COP) के 24वे सत्र का परिणाम सकारात्मकः भारत
- छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति द्वारा वनोपज एवं पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का प्रमाणीकरण
- छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ वन मण्डल अंर्तगत छाल खुली खदान परियोजना क्षेत्र में विभिन्न मौसमों में पक्षियों की विविधताओं का अध्ययन
- जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा धमतरी वन मंडल क्षेत्र में 3 दिवसीय बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।
- समाचार शीर्षक

जलवायु परिवर्तन के नन्हें शिकार

सिर्फ पेड़–पौधे और जीव जंतु ही जलवायु परिवर्तन के शिकार नही है, अपितु सूक्ष्म जगत् भी जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हो रहे है। तापमान के बढ़ने से सूक्ष्मगत को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। इन छोटे–छोटे जीव–जंतुओं में ऐसे कई जीव है जो की प्रकृति परागण प्रकिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है तथा इनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है यदि इसकी रोकथाम नही की गयी तो प्रकृति में पाए जाने वाली विविधता भी खतरे में पड़ सकती है। इन सभी परागणकारी जंतुओ मे सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खी है जिन्हे तापमान के बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। धरती के स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए मधुमक्खियां बहुत आवश्यक है । धरती में 30,000 प्रजातियां पायी जाती है जो कि कृषि तथा जंगली पौधों के लिए लाभकारी है किंतु इनकी जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है इसका मुख्य कारण मानव विकास ,कीटनाशक का प्रयोग, तथा जलवायु परिवर्तन है।

मधुमक्खियां हजारों की संख्या में कालोनी में रहती है तथा विभिन्न प्रकार के पौधों से शहद बनाती हैं परंतु वर्षा के पैटर्न में बदलाव के कारण बाढ़, सूखा इत्यादि ने वृक्षों तथा पौधों की कई प्रजातियों को नष्ट किया है जिससे इसकी कालोनी बुरी तरह प्रभावित हुई है । हम इस तथ्य को नकार नही सकते कि ये परागणकारी प्रकृति के लिए कितने आवश्यक है और इसीलिए हमें अपने वजूद को कायम रखने लिए अपने अस्तिव, पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखना जरुरी है।

'' यदि मधुमक्खियां धरती से पूरी तरह से खत्म हो गई तो, मानव जीवन में सिर्फ 4 वर्ष शेष बचेगे।''
– अल्बर्ट आइस्टीन

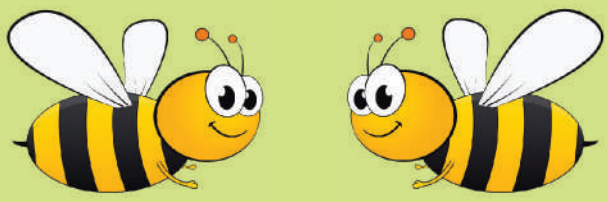

नेहा श्रीवास
जलवायु परिवर्तन केन्द्र

माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री

Bhupesh Baghel
CHIEF MINISTER

मंत्रालय, महानदी भवन
अटल नगर, रायपुर, 492002, छत्तीसगढ़
फोन: +91 (771) 2221000, 2221001
ई–मेल : cmcg@nic.in

Mantralaya, Mahanadi Bhawan,
Atal Nagar, Raipur, 492002, Chhattisgarh
Ph.: +91 (771) 2221000, 2221001
E-mail : cmcg@nic.in

Do.No. 24 Date : 07.01.2019

::संदेश::

छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है। एक ओर लगभग 44 प्रतिशत वनक्षेत्र तो दूसरी ओर महानदी, गंगा, गोदावरी, नर्मदा और ब्राहमणी नदी बेसिन प्रदेश के समृद्वता के प्रतीक हैं। अपने प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वैभव एवं पारम्परिक ज्ञान की प्रचुरता के फलस्वरुप छत्तीसगढ़ राज्य संपूर्ण विश्व में अद्वितीय स्थान रखता है।

विगत वर्षो में पृथ्वी की जलवायु में तेजी से परिवर्तन हुआ है तथा छत्तीसगढ़ राज्य में भी इसका व्यापक असर देखा जा सकता है। मौसम चक्र तेजी से बदल रहा है। मानसून के आने का समय निश्चित नही रहा है और बारिश की अवधि भी कम हो गयी है, जिसका प्रमुख कारण अंधाधुंध औद्योगिकीकरण, तकनीकी कुप्रंबधन एवं पर्यावरण प्रतिकूल जीवनशैली है।

कई दशकों में हुए इस परिवर्तन को हम एकाएक ठीक नही कर सकते। परंतु पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों पर नियंत्रण कर, बदलते जलवायु के अनुसार खुद को ढ़ालकर और जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने वाले उपायों को अपनाकर हम काफी हद तक दुनिया और मानव जाति को कई खतरों से बचा सकते है।

मुझे यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि राज्य में जलवायु परिवर्तन एवं उससे होने वाले प्रभावों से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र विभिन्न शासकीय विभागों से तालमेल स्थापित कर सुनियोजित तरीके से कार्य कर रहा है एवं पारम्परिक ज्ञान एवं जीवनशैली की वैज्ञानिकता आधारित प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों में जलवायु परिवर्तन संबंधी जागरुकता फैलाने एवं केन्द्र द्वारा किये गए प्रयासों की जानकारी जनमानस तक पहुंचने हेतु त्रैमासिक न्यूज लैटर का प्रकाशन कर रहा है जो एक सराहनीय कदम है।

त्रैमासिक न्यूजलैटर के आगामी अंक हेतु मेरी असीम शुभकामनायें।

(भूपेश बघेल)

माननीय वन मंत्री जी का संदेश

मोहम्मद अकबर
मंत्री
आवास एवं पर्यावरण, वन
परिवहन, खाद्य, नागरिक
आपुर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
विभाग

मंत्रालय : कक्ष क्र. एम 3 - 13,14, 15
निवास : B-5/10 मेन रोड शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
दूरभाष : 0771-2510321 (कार्यालय)
0771-2221321 (फैक्स)
दूरभाष : 0771-2331326 (निवास)
0771-2331505 (फैक्स)

क्रमांक 08

रायपुर दिनांक 05/01/2019

:: संदेश ::

जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिये एक गंभीर समस्या बन गया है तथा इसके दुष्परिणाम स्पष्ट रुप से परिलक्षित हो रहे हैं। उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा के साथ–साथ तीव्र और गंभीर सूखा जैसी घटनाओं मे वृद्धि हो रही है। विकासशील एवं अविकसित देश पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहे है।

छत्तीसगढ़ राज्य भी जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से अछूता नही है। राज्य में जलवायु परिवर्तन का व्यापक असर कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में देखने मिला है जिसके कारण स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। अनियोजित औद्योगिकीकरण एवं यांत्रिक विकास को भी तार्किक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। राज्य में सदियों से प्रचलित पारम्परिक ज्ञान एवं पर्यावरण हितैषी जीवनशैली की वैज्ञानिक प्रमाणिकता को सिद्ध करके उसे अपनाने एवं उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करना जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से निपटने में सहयोगी भूमिका निभा सकता है।

यह बड़े ही हर्ष का विषय है कि छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के द्वारा समस्त संबंधित विभागों से तालमेल स्थापित कर राज्य स्तरीय कार्ययोजना के माध्यम से राज्य में जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से निपटने के लिये व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन केन्द्र के द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी जानकारी सहित स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु त्रैमासिक न्यूज लैटर का हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशन किया जा रहा है।

यह त्रैमासिक न्यूज लैटर अपने उद्देश्यों में सफल हो तथा जलवायु परिवर्तन के ज्ञान के विकास एवं जनोन्मुखी क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित हो, इन्ही शुभकामनाओं के साथ.....

(मोहम्मद अकबर)

पर्यावरण मंत्रालय ने हरित दिवाली –स्वस्थ दिवाली अभियान का शुभारंभ किया

वायु प्रदूषण, सर्दियों के दौरान देश में, विशेषकर उत्तरी हिस्सों में गंभीर स्वास्थ्य समस्या का रुप धारण कर लेता है। धूल कण, कुछ राज्यों में पराली जलाने, कचरा सामग्री जलाने और मौसम से जुड़ी स्थितियों के कारण ही देश के उत्तरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ जाता है। इस वायु प्रदूषण से बच्चों,बुजुर्गो और सांस की बीमारियों से पीडित लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। लोग इसी अवधि के दौरान प्रकाश उत्सव 'दीपावली' को भी काफी धूमधाम से मनाते है तथा ज्यादातर लोग पटाखे जलाकर ही दीपावली मनाना पंसद करते है। पटाखों में कई ज्वलनशील रसायन होते है जिनमें पोटेशियम क्लोरेट पाउडर वाला एल्युमिनियम , मैग्नीशियम, बेरियम, तांबा, सोडियम, लिथियम, स्ट्रोंटियम इत्यादि शामिल होते है और इन रसायनों के जलने पर तेज आवाज के साथ बहुत ज्यादा धुआं भी निकलता है। इस धुएं और आवाज से बच्चों एवं बुजुर्गो की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गंभीर हो जाती है। इतना ही नही, यह धुआं पशुओं और पक्षियों के लिए भी नुकसानदेह होता है। इन प्रतिकूल प्रभावों के साथ–साथ दीपों के त्योहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय ने 'हरित –दिवाली' अभियान शुरु किया है।

इस अभियान का शुभारंभ वर्ष 2017–2018 में हुआ था। उस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, विशेषकर इको–क्लब से जुड़े बच्चों ने इस अभियान में भाग लिया था, और कम से कम पटाखे फोड़ने की शपथ ली थी। इस गहन अभियान के दौरान बच्चों को पर्यावरण अनुकूल ढंग से दीपावली मनाने की सलाह दी गई थी। बच्चों को इसके तहत अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों को मिठाइयों सहित पौधे उपहार स्वरुप देने और अपने घरों एवं आसपास के क्षेत्रों की सफाई करने की सलाह दी गई थी। यह अभियान अत्यंत सफल रहा और वर्ष 2016 के विपरीत वर्ष 2017 में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण ने विकराल रुप धारण नही किया था।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने इसी तरह का अभियान शुरु किया है। हालांकि इस वर्ष यह अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा। 'हरित दिवाली–स्वस्थ दिवाली', अभियान का विलय अब 'ग्रीन गुड डीड' अभियान में कर दिया गया है जिसका शुभारंभ पर्यावरण संरक्षण के लिए सामाजिक एकजुटता के रुप में किया गया है। मंत्रालय ने सभी स्कूलों और कॉलेजों को इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित किया है।

स्त्रोत : *http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1550280*

वैश्विक रिर्पोट की चेतावनी –भारत को बड़ा खतरा, जलवायु परिवर्तन का असर आशंका से कही ज्यादा बदतर

जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों से पर्दा हटाने वाली रिर्पोट माह अक्टूबर 2018 में क्लाइमेंट चेंज पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल (आईपीसीसी) द्वारा जारी की गई है। ग्लोबल वार्मिग अगर 2.7 डिग्री फारेनहाइट (1.5 डिग्री सेल्सियस) तक बढ़ जाएगा तो इसका असर आशंका से कही ज्यादा बदतर होगा। क्लाइमेंट चेंज पर इंटरगवर्नमेंटल पैनल (आईपीसीसी) अक्टूबर 2018 में दक्षिण कोरिया के इचियन में जारी एक व्यापक मूल्यांकन के आधार पर यह अंदेशा जाहिर किया गया। जलवायु परिवर्तन पर यह बहुत अहम समीक्षा रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में भारत के लिए भी बड़ी चेतावनी है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ऐसे हालात से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैस और कार्बन उत्सर्जन को कम करना ही होगा। जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों से आगाह करती इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि दुनिया का तापमान1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो भारत को साल 2015 की तरह जानलेवा गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा।

आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुमानों पर इस वर्ष दिसंबर में पोलेंड में जलवायु परिवर्तन पर होने वाली बैठक में चर्चा होगी। इस बैठक में दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये पेरिस समझौते की समीक्षा करेगें। सबसे बडे कार्बन उत्सर्जक देशों में से एक होने के कारण भारत इस वैश्विक बैठक में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

बढते तापमान पर खतरे की घंटी बजाते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि औसत वैश्विक तापमान 2030 तक 1.5 डिग्री के स्तर तक पहुंच सकता है।

स्त्रोत:- *AmarUjala. New Delhi Mon, 08 Oct 2018*

पार्टियों के सम्मेलन (COP) के 24वे सत्र का सकारात्मक परिणामः भारत

सभी पार्टियों ने 2020 के बाद 100 बिलियन डॉलर के निम्न मूल्य से नए सामूहिक वित्त लक्ष्यों की स्थापना पर सहमति जताई

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना संधिपत्र (COP 24) के पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र 2 से 15 दिसम्बर 2018 तक पोलैण्ड के काटोवाइस में आयोजित किया गया। यह एक प्रमुख सम्मेलन था जिसमें पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों/तौर तरीकों/ नियमों को अंतिम रुप देने 2018 के सुविधा प्रदान करने वाले तालानोआ संवाद के समापन एवं 2020 से पूर्व के कदमों के कार्यान्वयन एवं महत्वाकांक्षा के सर्वेक्षण सहित तीन प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

भारत ने पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के अपने वादे को दुहराते हुए सीओपी–24 के दौरान प्रतिबद्वता एवं नेतृत्व और जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए सामूहिक रुप से कार्य करने की भावना प्रदर्शित की। भारत विकसित एवं विकासशील देशों के विभिन्न आरम्भिक बिन्दुओं की स्वीकृति विकासशील देशों के लिए लचीलेपन एवं समानता सहित सिद्वांतों पर विचार और समान लेकिन विभेदकारी जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताओं सहित देश के प्रमुख हितों की रक्षा करते हुए सभी वार्ताओं में सकारात्मक एवं रचनात्मक तरीके से संलग्न रहा।

राष्ट्रीय रुप से निर्धारित योगदानों पर जारी दिशा–निर्देश, एनडीसी की राष्ट्रीय रुप से निर्धारित प्रकृति को संरक्षित करते है तथा पार्टियों के लिए अनुकूलन सहित विभिन्न प्रकार के योगदानों को प्रस्तुत करते है। इस विषय पर समग्र दिशा–निर्देश पेरिस समझौते के सिद्वांतों को प्रदर्शित करता है तथा उस नेतृत्व की स्वीकृति देता है जिसे विकसित देशो द्वारा पेरिस समझौते के उद्देश्यों को अर्जित करने के लिए प्रदर्शित किया जाना है।

अनुकूलन पर दिशा–निर्देश विकासशील देशों की संयोजन आवश्कताओं को स्वीकृति देता है और यह सीबीडीआर–आरसी के अति सफल सिद्वांत पर आधारित है। यह विशिष्टिकरण विकासशील देशों की अनुकूलन गतिविधियों को समर्थन देने के प्रावधानों को समावेशित करने के द्वारा संचालनगत किया गया हैं।

भारत एक मजबूत पारदर्शी व्यवस्था के पक्ष में है और अंतिम रुप से संवर्धित पारदर्शिता संरचना विकासशील देशों के लिए लचीलापन प्रदान करते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों पर आधारित है।

वित्तीय प्रावधानों पर दिशा–निर्देश विकासशील देशों को कार्यान्वयन के माध्यम प्रदान करने में विकसित देशों के उत्तरादायित्व को परिचालित करता है तथा जलवायु वित के नए एवं अतिरिक्त तथा जलवायु विशिष्ट होने की आवश्यकता की स्वीकृति देता है। पार्टियों ने 100 बिलियन डॉलर के निम्न मूल्य से 2020 के बाद नए सामूहिक वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना पर कार्य शुरु करने पर भी सहमति जताई है।

प्रौद्योगिकी के लिए सफल संरचना में संरचना के परिचालन की दिशा में अधिक समर्थन की आवश्यकता स्वीकार की गई है तथा यह प्रौद्योगिकी विकास एवं अंतरण के सभी चरणों को व्यापक रुप से कवर करता है।

भारत सीओपी–24 के परिणाम को सकारात्मक मानता है जो पार्टियों की चिंताओं पर ध्यान देता है तथा पेरिस समझौते के सफल कार्यान्वयन की दिशा में कदम आगे बढ़ाता है।

स्त्रोत:-*http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1556087*

छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति द्वारा वनोपज एवं पारंपरिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का प्रमाणीकरण

जलवायु परिवर्तन शाखा की NAFCC परियोजना अंर्तगत चयनित तीन जिलों – धमतरी,बलौदाबजार तथा महासमुंद वनमण्डलों के अधीन चिन्हांकित की गयी संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के द्वारा संग्रहित लघुवनोपजों के प्रमाणीकरण अंर्तगत धमतरी वनमण्डल के दुगली परिक्षेत्र के जबर्रा,मुनईकेरा तथा दिनकरपुर वन समितियों का पंजीयन किया गया है। जिसमें से धमतरी वनमण्डल के चयनित समितियों का निरीक्षण सम्पन्न करने उपरांत स्कोप सर्टीफिकेट जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है । जिसमें उस क्षेत्र के प्रमुख वनोपजों के प्रमाणीकरण पश्चात् केवल हर्रा, बहेड़ा एवं आंवला को क्रमशः 36 रु., 16रु. एवं 110रु. प्रति किलोग्राम विक्रय किये जाने हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समिति द्वारा सहमति दी गयी एवं संग्रहण की जा रही वनोपजों की जैविक गुणवत्ता का निर्धारण **NPOP** (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम) मानक के अनुरुप किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बलौदाबाजार वनमण्डल के अंर्तगत चयनित समितियों का निरीक्षण /पंजीयन का कार्य किया जा रहा है।

वन मण्डल – धमतरी					
क.	वन परिक्षेत्र	ग्राम वन प्रबंधन समिति	कुल संग्रहण रकबा (हे.)	प्रमुखतः वनोपज	मात्रा (मै.टन)
1	दुगली	दिनकरपुर, मुनाईकेरा, जबर्रा	4813.55	हर्रा	**0.3**
2				बहेडा	**0.2**
3				कालमेघ	**2.6**
4				सफेद मुसली	**5**
5				काली मुसली	**0.5**
6				तीखुर	**5.5**
7				नागरमोथा	**0.2**
8				ईमली	**5**
9				भेलवाजड़ी	**2**
10				शहद	**0.6**
11				साल बीज	**6**
12				चरोटाबीज	**0.4**

इसके अतिरिक्त पारम्परिक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के प्रमाणन हेतु सीजीसर्ट द्वारा कार्मिक निकाय (Personal Certification Body) की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार सीजीसर्ट द्वारा मैन्युल तैयार कर भारतीय गुणवता परिषद, नई दिल्ली को दिनांक 30/08/2018 को आवेदन भेजा जा चुका है । जिसके आधार पर आगामी कार्यवाही हेतु शीघ्र ही मूल्यांकनकर्ता दल का आगमन सीजीसर्ट कार्यालय में आना संभावित है ।

TCHPs प्रमाणिकरण के निम्न चरण है :–

1- TCHPs के आवेदन का पंजीयन

2. दक्षता मूल्यांकन

3. बाह्य मूल्यांकन

4. प्रमाणन पर निर्णय

5. निगरानी

6. निलंबन/प्रमाण पत्र जारी करना

छत्तीसगढ़ के धरमजयगढ़ वन मण्डल अंर्तगत छाल खुली खदान परियोजना क्षेत्र में विभिन्न मौसमों में पक्षियों की विविधताओं का अध्ययन

पारिस्थितिक तंत्र में पशु पक्षियों का महत्वपूर्ण स्थान है, वे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के अभिन्न अंग हैं। वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ पक्षी मुख्य रूप से पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तथा अन्य पक्षी छोटे जन्तु, जैसे कि कीड़े या केंचुए इत्यादि खाते हैं। पक्षीयो और उनके अंडो को कुछ जानवर भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं जैसे लोमड़ी, रैकून और सांप। एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी जानवरों के बीच खाद्य श्रृंखला किसी भी एक प्रजाति को बहुत अधिक वृध्दि करने से रोकने में मदद करते हैं। प्रकृति के इस संतुलन को बनाए रखने में पक्षी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खाद्य जाल के महत्वपूर्ण अंग होने के अलावा, पक्षी पारिस्थितिक तंत्र में भी भूमिका निभाते हैं।

जबकि खनिज संसाधनों हेतु खनन ही एक मात्र प्रकिया है जिससे खनिज प्राप्त किया जा सकता है जो सभी देशों के लोगों का जीवन स्तर को बनाए रखने और सुधारने के लिए आवश्यक हैं। खनिज संसाधन उस क्षेत्र में रोजगार, लाभांश और व्यक्तिगत आय को सुधारने में अपना योगदान प्रदान करता है जो स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए जरूरी है। खनन क्षेत्र प्रशिक्षित कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करता है और साथ ही व्यापारी, संबधित व्यवसायों को आरंभ कर सकते हैं।

खनन के प्रभाव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें खनन प्रक्रियाओं से उत्पन्न रसायनों द्वारा क्षरण, जैव विविधता की हानि और मिट्टी का क्षरण, भूजल और सतही जल का प्रदूषण शामिल है। कुछ मामलों में, अतिरिक्त मृदा का उपयोग निर्माण कार्यो में खदानों के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है ताकि रखे गए मलबे और मिट्टी के भंडारण के लिए जगह बनाया जा सके। रसायनों के रिसाव कों यदि ठीक से नियंत्रित न किया जाए तों खनन के संदूषण सें स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है खनन गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण के उदाहरणों में कोयले की आग शामिल है, जो वर्षों या दशकों तक रह सकती है, तो इससे भारी मात्रा में पर्यावरणीय क्षति हो सकती है।

उपरोक्त संदर्भ के मद्देनजर, राज्य वन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर द्वारा ओसीपी छाल के खनन क्षेत्रों में पंक्षियों के वैकल्पिक निवास स्थान का अध्ययन किया गया है अध्ययन का उद्देश्य खनन क्षेत्र के प्रभावित पक्षियों के लिए एक उपयुक्त वैकल्पिक आवास प्रदान करना है। वैकल्पिक निवास स्थान को तैयार करने से पहले, खनन क्षेत्रों की मौजूदा पक्षी प्रजातियों का विभिन्न मौसमों में पक्षीयों का अध्ययन करना आवश्यक है। इसलिए, अनुसंधान दल द्वारा लाइन ट्रांजेक्ट विधि से विभिन्न मौसमों में खनन क्षेत्रों का क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया है जिसमें वन क्षेत्र और इसके आसपास मीटर का लाइन ट्रांजेक्ट बनाया गया है। पंक्षियों के 1200 मीटर पथ अवलोकन में, वन्यजीव प्रजातियों और निवास स्थान के अध्ययन को अलग–अलग अंतरालों में लिया गया है। जिसमे 0 मी, 300 मी, 600 मी, 900 मी, और 1200 मी शामिल है।

मौसमी विविधताओं के अध्ययन गर्मी के मौसम में 61 पक्षी प्रजातियों के कुल 405 पक्षियों को देखा गया जबकि सर्दी के मौसमी सर्वेक्षण में 92 प्रजातियों के कुल 776 पक्षियों को देखा गया, दोनों सर्वेक्षणों के विश्लेषण के दौरान 61 में से 12 प्रजातियां जो गर्मी के मौसम में उपस्थित थे वह सर्दी के सर्वेक्षण में अनुपस्थित पाए गए इसी तरह पक्षियों की 92 प्रजातियों में से 40 प्रजातियां सर्दी के मौसम में देखे गए परंतु गर्मी के मौसम में नही देखी गईं।

खनन क्षेत्रों और इसके आस–पास के क्षेत्र में मौसमी भिन्नता के परिणामस्वरूप, दो अलग–अलग मौसमों के दौरान 105 पक्षी प्रजातियों के कुल 1181 पक्षियाँ देखे गए हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों और वन्यजीवों की स्थिति भी अलग–अलग मौसम के दौरान देखी गई और उनका विश्लेषण किया गया है। उपरोक्त अध्ययन से पता चलता है कि पक्षी प्रजातियों में दो सर्वेक्षणों में बहुतायत से भिन्नता की स्थिति मौसमी/जलवायु पर निर्भर करती है।

Scally Breasted Munia

Oriental Turtle Dove

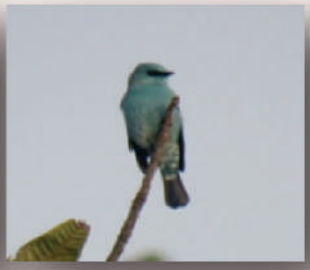

Verditer Flycatcher

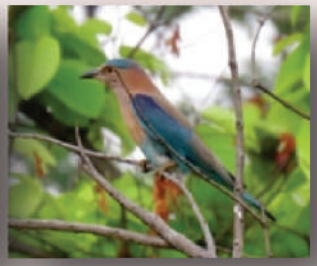

Indian Roller

Yellow Wattled Lapwing

द्वारा:– आशुतोष पाण्डेय, एस.आर.एफ. तथा विजय भगत, जे.आर.एफ. रा.व.अ.प्र.सं., रायपुर

जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा धमतरी वन मंडल क्षेत्र में 3 दिवसीय बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

संग्रहित वनोपज(शतावार)

पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित ''राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष'' अंतर्गत आने वाले परियोजना क्षेत्र ग्राम मुनाईकेरा, जबर्रा, दिनकरपुर एवं ग्राम भोभलाबहरा एवं परिक्षेत्र कार्यालय दुगली वनमण्डल धमतरी में दिनांक 28—11—2018 से 30—11—2018 तक बैठक सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्य क्रमशः वन प्रबंधन समिति मुनाईकेरा, जबर्रा, दिनकरपुर एवं भोभलाबहरा में दिनांक 28/11/18, 29/11/18 एवं 30/11/18 को प्रवास के दौरान आयोजित किया गया। श्री प्रमोद कुमार संगल प्रो.नेचरसोल हैल्थ केयर तकनीकी सलाहकार, श्री शिरीष कुमार सिंह फील्ड इंस्पेक्टर, सीजीसर्ट, श्री राकेश कुमार श्रीवास जे.आर.एफ जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा प्राथमिक वनोपज समितियो/वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों का क्षमता उन्नयन एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ ही वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के संग्रहण एवं उनके जैविक प्रमाणीकरण के संबंध में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में कुल 90 प्रतिभागी उपस्थित रहे जिसमें वन विभाग के स्थानीय कर्मचारी एवं संग्राहक समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में— श्री राकेश कुमार श्रीवास जे.आर.एफ जलवायु परिवर्तन केन्द्र द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को क्षेत्र में संचालित परियोजना की जानकारी दी गई। जलवायु अनुकूलन एवं जलवायु अनुकूलित आजीविका विकास की गतिविधियों तथा वनोपज के विनाश विहीन संग्रहण करने हेतु उपायों पर चर्चा की गई। तत्पश्चात् श्री प्रमोद कुमार संगल तकनीकी सलाहकार द्वारा वनोपज संग्रहक सदस्यों को वनोपज के संग्रहण, भंडारण एवं उसके रखरखाव पर प्रशिक्षण दिया गया।

श्री शिरीष कुमार सिंह द्वारा प्राथमिक लघु वनोपज संग्राहकों से उनकी वन प्रबंधन समितियों द्वारा संग्रहित किए जाने वाले वनोपज उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण के महत्व पर संक्षिप्त जानकारी एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को उपस्थित प्रतिभागियों को समझाया गया। बैठक सह प्रशिक्षण उपरांत ग्राम जबर्रा में उपस्थित प्रतिभागीयों को शतावर(स्थानीय भाषा में दशमूल कंद) को निकालने व साफ—सफाई कर उसकी गुणवत्ता बनाये रखने की प्रक्रिया को प्रायोगिक रुप से समझाया गया।

वनोपज की पहचान एवं संग्रहण के तरीको पर प्रशिक्षण

संग्रहाकों के साथ बैठक सह प्रशिक्षण देते हुये ।

india फोकस

मंगलवार 09 अक्टूबर 2018 12

रिपोर्ट: केंद्र ने यूएन रिपोर्ट का समर्थन करते हुए कहा कि भारत पहले ही जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना कर रहा है

ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ चाहिए एकजुटता

भारत सरकार की ओर से आग्रह किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अमरीका सहित सभी देशों को एक वैश्विक समुदाय की तरह काम करना होगा। देश ने इस वास्तविकता से भी इंकार नहीं किया भारत सहित दुनिया के कई हिस्से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना पहले से ही कर रहे हैं, जबकि भविष्य में स्थिति और विकट हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आइपीसीसी) की विशेष रिपोर्ट के निष्कर्षों का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि देश पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के जोखिम में है।

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की रिपोर्ट 'ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री' के निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देते हुए पर्यावरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ए. के. मेहता का कहना है कि भारत पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहा है। रिपोर्ट ने पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री वृद्धि के भीतर ग्लोबल वार्मिंग को बनाए रखने के लिए उद्योग, ऊर्जा, परिवहन सहित अन्य सभी क्षेत्रों में तेजी से और पर्याप्त परिवर्तन की सिफारिश की है। गौरतलब है कि 91 लेखकों और 40 संपादकों की ओर से तैयार आइपीसीसी रिपोर्ट के आने से पहले अमरीका जैसे विकसित देश ने इसके निष्कर्षों और सिफारिशों को लेकर सवाल उठाए थे।

भारत पर कहीं ज्यादा जोखिम

आइपीसीसी रिपोर्ट देशवार प्रभावों की सूची नहीं देती है। लेकिन कई वैज्ञानिक शोध के अनुसार भारत जलवायु परिवर्तन प्रभावों के लिए सबसे कमजोर है। जादवपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर और आइपीसीसी रिपोर्ट की सह-लेखक जयश्री रॉय के अनुसार, 'हमने पाया है कि ग्लोबल वार्मिंग का बोझ उन गरीबों पर असमान रूप से पड़ेगा, जो समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अगर हम 1.5 डिग्री के लक्ष्य को हासिल नहीं करते तो सबसे अधिक प्रभावित बड़े शहर, तटीय क्षेत्र, पहाड़ और छोटे द्वीप वाले क्षेत्र होंगे। कोयले, डीजल, जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग शहरों में गर्मी को बढ़ा सकता है।

कार्बन उत्सर्जक देशों में से एक भारत के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना एक बड़ी जरूरत है क्योंकि देश न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पहले से महसूस कर रहा है, बल्कि समूचे विश्व से आग्रह कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई को एकजुट होकर लड़ा जाए।

देश के लिए वास्तविक खतरा माना गया जलवायु परिवर्तन!

पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ए. के. मेहता का कहना है, 'भारत जलवायु परिवर्तन को वास्तविक खतरा मानता है और इसके प्रभावों को कम करने के लिए हम जो भी कर सकेंगे, वह करेंगे, एक राष्ट्र के तौर पर हम पूरे प्रयास करेंगे।' रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गरीबी भी बढ़ेगी और अगर ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है तो खाद्यान्न फसलों में कमी को भी थामा जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में चेताया गया है कि भारत को हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते 2015 में भी हजारों लोगों की जान चली गई। जलवायु परिवर्तन की देन इस तरह के जोखिम से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैस और कार्बन उत्सर्जन को कम करना ही सबसे उचित कदम है, जिस पर तत्काल कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना जरूरी

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग में 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के परिणाम विनाशकारी होंगे। 1.5 डिग्री वृद्धि के परिणामों में कई क्षेत्रों में चरम तापमान, आवृत्ति, तीव्रता, या कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की मात्रा और कुछ क्षेत्रों में तीव्रता या सूखे की आवृत्ति में वृद्धि शामिल है लेकिन 2 डिग्री वृद्धि के प्रभाव बहुत खतरनाक हो सकते हैं। आइपीसीसी के अनुसार, 2 डिग्री सेंटीग्रेट की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 सेल्सियस पर रखे जाने से 2100 तक वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि में 10 सेमी की कमी आएगी। कोरल रीफ्स 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग के साथ 70 -90% तक गिर जाएगी, जबकि लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होती है तो यह पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

पत्रिका Tue, 09 October 2018
epaper.patrika.com/c/34924045

सम्पादक मंडल

y ? DIC A S Q S{H D B D G = |
y & D D Q 1 " K D
y & D O ? N R > # A H D % K H
y # A < A > : M
y # A D N E M , N A
y O ? ! D N H S @ ? C

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर
विधानसभा के पास, बलौदा बाजार रोड, जीरो प्वाइंट
रायपुर – 493111, छत्तीसगढ़
फोन : 0771 – 2285120
ईमेल: chhattisgarh.sccc@gmail.com
वेबसाइट : www.cgclimatechange.com